REFERENCE TO THE REVISED OFFICE HOURS DURING ASIAD

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman(S'r, after the serious subject of science and technology, it is proper that we go to a lighter subject—and I am happy that you are in the Chair- 'because the subject I am dealing with is not normally dealt with and tbat is sports.

The Government have announced that the working hours of offices during the "Asiad will be from ll a jn. to *S* p.m. This has caused great dismay amongst the Government emp'oyees because you know that Asiad is considered to be most important sporting event ever held in the country. None of the Government employees will be able to see it either in the field or through the media. The first discipline in Asiad normally starts at 9 a.m. and the last discipline, football, starts at 7.00 and if you make the office hours* from ll a.m, to 6 p.m., none of the Government employees will be able to enjoy] any of the disciplines. Sir, in a state of affairs where we consider Asiad is not so much importaut that Parliament's session is proponed—which is considered to be extraordinary and against which we protested from this side of the House—ive feel that te deny the opportunity to Government employees will be something which I find yery difficult to accept and I think that the Government employees can be given a fair opportunity of watching it by shifting the office timing. For example, if we make the office hours from 10 a.m. (to 2 p.m. or 9 a.m. to 2 p.m., a large number of employees will be able to witness the games in the field and also through the TV. Also it has been toid to us that if the office hours are extended uP to six, at six p.m. in November it will be dusk and with the Push of commuters going from one stadium to aether, the office, goers would find it extremely difficult to reach their homes and lady employees of Demi will be realiy ln difficulty because they may got a bus only at nine or ten in the hight and you know in Delhi what distances people come from. Therefore, I would draw the attention of the Government to change the office timings suitably so that Government employees of Delhi also have an opportunity of witnessing some events in the field as well as in the media because he announced change of timings will completely create a sense of frustration amongst them.

REFERENCE TO THE REPORTED NON-PAYMENT OF FULL PRICE OF SUGARCANE BY SUGAR MILLS TO THE SUGARCANE GROWERS

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस माननीय सदन का और सरकार का ध्यान अपने देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के सामने का प्रश्न उपस्थित है, उसकी ओर मुखातिब करना चाहता हूं । हमारे देश में गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों का 73 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी पड़ा हुआ है । यह गन्ना पिछले सीजन में सप्लाई किया गया था । नया सीजन नवम्बर में शुरू होगा । इन 73 करोड़ रुपयों में उत्तर प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा है । जिन चीनी मिलों के पास यह बकाया राशि है उनमें सहकारी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट क्षेत्र की मिलें भी हैं और शुगर कारपोरेशन क्षेत्र की चीनी मिलें भी हैं । इतनी बड़ी रकम बकाया पड़ी हुई है । इस रकम को किसानों को देने का जब निर्णय लिया जाएगा तो गन्ना उत्पादकों को उसका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, जब कि किसान जो खाद और बीज सरकारी गोदामों से, चीनी मिलों से या सहकारी समितियों से उधार लेता है उस पर आपको ताज्जुब होगा कि 18 प्रतिशत

[श्री शान्ति त्यागी]

सूद गन्ना किसानों को अदा करना पड़ता है। यह 73 करोड़ रुपया 6 महीने का है साल भर का कितना सूद होगा यह तो मैं केलकुलेट नहीं कर सकता हूं, इतना हिसाब मैं नहीं जानता, बहुत से माननीय सदस्य होंगे और आप स्वयं, इसको केलकुलेट कर सकते हैं। मौजूदा सरकार किसानों का मैन्डेट लेकर आई है, मजदूरों का मैन्डेट लेकर आई है। मैं समझता हूं कि लेवी की जो चीनी है उसके दाम शायद थोड़े से अर्से में तीन दफे बढ़ाये गये हैं और भी बहुत सी रियायतें उनको दी गई हैं, मगर किसानों का बकाया पड़ा है। वह ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं। जिस रेट पर गन्ना सप्लाई किया गया है उस रकम को वह मांग रहे हैं जिसको कम से कम 6 महीने मिल की तिजोरी में पड़े हुये हो गये हैं। यह अन्याय की बात है। इस बारे में किसानों के जलूस, किसानों की सभायें, उनका डेपूटेशन, और रेजोल्यूशन रोज ही अलग-अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान के अन्य भागों में हो रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इस रकम को अविलम्ब अदा कराये।

अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गुड़ और गन्ना हमेशा इस सदन में और दूसरे सदन में प्रश्न उठते रहते हैं और आज यह इस देश की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न, उनको खाद और बीज सस्ते दामों पर मिले यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर गुड़ और गन्ने के लिये एक अलग मंत्रालय न भी बना सकें तो इसके लिये एक अलहिदा विभाग कायम किया जाये।

अंत में मैं आपसे कहूंगा कि इस दफे गन्ने के दाम, यह सरकार के लिये शोभा की बात होगी और मैं समझता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री भी चाहती हैं कि पिछली दफा 20.50 रुपये क्विंटल इनको रेट दिया गया, इस साल इससे ज्यादा इनको दिया जाये। महोदय, अगला सीजन शुरू होने वाला है। मेरी समस्त माननीय सदस्यों, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से भी और अपोजीशन के सदस्यों से भी दरख्वास्त है कि वह सरकार से निवेदन करें कि इस साल पिछले सीजन के बनिस्पत उनको ज्यादा दाम मिलने चाहिएं, कम नहीं मिलने चाहिएं। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साइंस, कौसमिटिक, रबड़ इन पर दिन भर बहस होती रहती है। मगर उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस देश में 80 फीसदी लोग देहातों में रहते हैं और वे किसान हैं और मजदूर हैं। इसलिये उनके हितों के बारे में जब राज्य सभा में प्रश्न उठते हैं तो ऐसे मसलों पर थोड़ा सा वक्त आप ज्यादा दें यह समझकर कि ये बहुत बड़ी समस्यायें हैं। जो कास्मिटिक है, ड्रग्स है उनके बनिस्पत किसानों के संबंधित जो मामले हैं, जो प्रश्न हैं उनके लिये अवश्य ही ज्यादा टाइम अलाट किया जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका शुक्रिया।

REFERENCE TO THE REPORTED CLASHES BETWEEN AKAL] SATYAGRAHIS AND POLICE iN PUNJAB JAILS

DR (SHRIMATI) RAJENDER KAUR (Punjab); Mr. Vice-Chairman, Sir, ther$_e$ have been report$_s$ in the